(d) The sales of shares of these companies have been carried out on the basis of the prevailing market prices.

Oil exploration by private parties

2587. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is a sharp increase in reserves given to private parties for exploration of oil;

(b) if so, the details thereof, party-wise;

(c) whether it is a fact that earlier estimate of reserves was nearly half of what is estimated now;

(d) who did the estimation earlier and who has done the same now; and

(e) does it mean that there is any loss to Government in charging the fees based on the lower estimate of reserves earlier?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (d) While initial in place reserves in most of the fields awarded to Joint venture/private parties have increased, it has also decreased in some fields.

As per the initial estimation by ONGC/OIL, the reserves in joint venture fields was 421.248 million metric tonnes (MMT). This has increased to 497.77 as on 1.4.98 as per estimation by the Operator/DGH/JV.

In the case of private fields the initial estimation by ONGC was 23.682 MMT. This has increased to 61.695 to 84.034 MMT as on 1.4.98 as per estimation by DGH/Operator.

(e) No, Sir.

Alliance between IOC and ONGC

2588. SHRI PRAFULL GORADIA: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal for a strategic alliance between the IOC and ONGC;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what impact is it going to have on the working of these two public sector companies?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) and (b) Yes, Sir. There is a proposal for a corporate strategic alliance between IOC and ONGC, according to which IOC and ONGC have presently decided to acquire 10% shareholding of each other.

(c) The alliance would help synergise their operations for the common good of both and partake of current international trends of mutuality in working in the hydrocarbon sector. It could be a forerunner to possible vertical integration and help both companies to enhance their global standing and core competencies from "drilling to dispensing." While retaining focus on respective core business and competencies, both IOC and ONGC would explore investment options for securing assured growth and profitability.

Proposal to Hook-up pipelines

2589. SHRI LAJPAT RAI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government propose to hook-up the Kandla-Bhatinda and the Mathura-Ambala-Jalandhar pipelines;

(b) if so, the details thereof and progress so far made in this project;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) the estimated amount of expenditure involved therein?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR): (a) to (d) Kandla-Bhatinda Pipeline has already been hooked up at Panipat to Mathura-Ambala-Jalandhar Pipeline in May, 1996. The completion cost of the project was Rs. 17.45 crores.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्यीय राजमार्गों पर पेट्रोल पम्प

2590. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों तथा राज्यीय राजमार्गों पर चल रहे पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है और इनकी स्थापना एवं आबंटन संबंधी मानदंड क्या-क्या हैं,

(ख) क्या इनकी संख्या उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने की दृष्टि से पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अतिरिक्त पेट्रोल-पम्प खोलने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) (क) उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर 1142 खुदरा बिक्री केन्द्र प्रचालन में हैं। तेल उद्योग राज्य एंव राष्ट्रीय राजमार्गों पर खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें स्थापित करने के लिए निम्नलिखित परिणाम-दूरी मानकों का अनुसरण करता है:

(1) प्रस्तावित खुदरा बिक्री केन्द्र के 15 किलोमीटर (दोनों तरफ) के अंतर्गत प्रति खुदरा बिक्री केन्द्र संयुक्त थूपुट 80 किलो लीटर (के एल) से अधिक होना चाहिए।

(2) प्रचालन के दूसरे वर्ष के दौरान न्यूनतम प्रत्याशित बिक्री निम्नवत होनी चाहिए:

(क) केवल एच एस डी के मामले में	-	50 किलो लीटर प्रति माह
(ख) एम एस/एच एस डी के संयुक्त मामले में	-	एम एस - 5 किलोलीटर प्रतिमाह
	-	एच एस डी 50 किलोलीटर प्रतिमाह

(ख) और (ग) वर्द्धित मांग को पूरा करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1996-98 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के लिए 98 और खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें सम्मिलित की गई हैं।

निजी क्षेत्र के अंतर्गत तेलशोधक कारखानों की स्थापना

2591. **श्री गोविन्दराम मिरी:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में निजी क्षेत्र के अंतर्गत तेलशोधक कारखानों की स्थापना के लिए दी गई स्वीकृति के आधार पर अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन तेल शोधक कारखानों में से प्रत्येक की संस्थापित क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) इन तेलशोधक कारखानों को स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं और प्रत्येक तेलशोधक कारखाने में पूंजीगत निवेश में विदेशी एवं स्वदेशी ऋण का प्रतिशत कितना-कितना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) गुजरात में मैसर्स रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड और मैसर्स एस्सार आयल लिमिटेड की रिफाइनरियां, जो दोनों जामनगर में स्थित हैं, क्रमश: जून, 1999 तथा मार्च, 2000 तक आरंभ कर दिए जाने की संभावना है।

मैसर्स इंटरनेशनल पेट्रोलियम एस ए (बी वी आई), स्विटजरलैंड को गुजरात के पश्चिम तट पर 100 प्रतिशत निर्यात मूलक इकाई के तहत 5 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए 14.8.1992 को एक औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किया गया था। लेकिन, चूंकि रिफाइनरी ने कोई प्रगति नहीं की इसलिए उनके आशय-पत्र का पुन: वैधीकरण नहीं किया गया।

सरकार ने दिसंबर, 1995 में ओमान आयल कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में बीना (म. प्र) में 5277 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 6 एम एम टी पी ए क्षमता वाली रिफाइनरी की स्थापना के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। क्रूड पाइपलाइन बिछाने के लिए वन्य जीवन रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गुजरात सरकार से समुद्री अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

पश्चिम तट रिफाइनरी महाराष्ट्र में 6 एम एम टी पी ए क्षमता के साथ हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और ओमान आयल कंपनी के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित की जानी थी पर ओमान आयल कंपनी ने अपनी विभिन्न अन्य वचनबद्धताओं के कारण इस उद्यम में अपने हित की समीक्षा करने की इच्छा व्यक्त की । रीतियों की जांच एच पी सी एल द्वारा की जा रही है।

सीसा-रहित पेट्रोल

2592. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीसा-रहित पेट्रोल की बिक्री कितने शहरों में की जा रही है और कितने शहरों में मात्र सीसा-रहित पेट्रोल का उपयोग अनिवार्य है;

(ख) देश में बेचे जाने वाले कुल पेट्रोल की तुलना में सीसा-रहित पेट्रोल की बिक्री का प्रतिशत कितना है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रमाणिक अध्ययन किया गया है कि सीसा-रहित पेट्रोल ही प्रदूषण नियंत्रण का एकमात्र उपयोगी विकल्प है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): (क) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार सीसा रहित पेट्रोल 412 स्थानों पर बेचा जा